



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940

No. 308]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

मामला सं. ओआई (सीवीडी)-04/2018

विषय : इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से कांटिनेंशियन कास्ट कापर वायर राइस के आयातों से संबंधित सब्सिडी रोधी जॉच की शुरूआत

**फा. सं. 6/17/2018-डीजीएडी.**—यतः मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और मै.वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाइट कापर) (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उन पर पारनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से कांटिनेंशियन कास्ट कापर वायर राइस (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए सब्सिडीरोधी जॉच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

### क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रदेशों की सरकारों और नगरपालिकाओं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों सहित संबद्ध देशों की सरकारों में विभिन्न सूतरों द्वारा प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडीयों से लाभ मिल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और संगत सरकारी एजेंसियों और लोक निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जॉचकर्ता प्राधिकारियों जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जॉच की थी और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी निर्धारित की थी, पर भरोसा किया है।

**ख. परामर्श**

3. एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अनुसार इंडोनेशिया की सरकार, मलेशिया की सरकार, थाइलैंड की सरकार और वियतनाम की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जॉच पूर्व परामर्श किया गया था। संबद्ध देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकार्ड में लिया गया है।

**ग. सब्सिडी कार्यक्रम**

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातिकों को संबद्ध देश की सरकार और /या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त नीचे यथा सूचीबद्ध अनेक सब्सिडी स्कीमों/कार्यक्रमों से लाभ मिला है।

**I. इंडोनेशिया के संबंध में स्कीमों की सूची****निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

कार्यक्रम संख्या 2: इंडोनेशिया एग्जिम से निर्यात वित्तपोषण

कार्यक्रम संख्या 3: निर्यातिकों को उनके नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति

**ऋण के रूप में अभिज्ञात योजनाएं:**

कार्यक्रम संख्या 5: मंडीरी बैंक द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण

क. कार्यक्रम संख्या 5 (क): निवेश ऋण

ख. कार्यक्रम संख्या 5 (ख): उद्यमी के लिए ऋण

**कर प्रोत्साहन और बैट छूट के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

कार्यक्रम संख्या 7: आयात शुल्क पर छूट

कार्यक्रम संख्या 8: आयात शुल्क वापसी

कार्यक्रम संख्या 9: लाभांश पर आयकर

कार्यक्रम संख्या 10: शुद्ध कर योग्य आय में कमी

कार्यक्रम संख्या 11: नुकसान को आगे ले जाना

कार्यक्रम संख्या 12: पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क के भुगतान का स्थगन।

कार्यक्रम संख्या 13: उत्पादन उद्देश्य के लिए कच्चे माल और सहायक वस्तुओं पर शुल्क छूट

कार्यक्रम संख्या 14: कुछ वस्तुओं के आयात पर आयकर से छूट अगर कंपनी एसईजेड में स्थित है।

कार्यक्रम संख्या 15: एसईजेड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आयकर में कमी

कार्यक्रम संख्या 17: पायनियर उद्योग का दर्जा

कार्यक्रम संख्या 18: सूचीबद्ध निवेश के लिए आयकर लाभ

**वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

कार्यक्रम संख्या 20: एसईजेड में स्थित उद्यमों के लिए भूमि कर में कटौती।

**II. मलेशिया के संबंध में योजनाओं की सूची****अनुदान के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

कार्यक्रम संख्या 1: बाजार विकास अनुदान

कार्यक्रम संख्या 2: विज्ञान निधि

कार्यक्रम संख्या 3: टेक्नो फंड

कार्यक्रम संख्या 4: इनो फंड

कार्यक्रम संख्या 5: आरंभिक निवेश कार्यक्रम

कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार

**निर्यात क्रेडिट और निर्यात वित्तपोषण के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

कार्यक्रम संख्या 7: निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त

कार्यक्रम संख्या 8: क्रेता क्रेडिट गारंटी

कर प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 9: पायनियर का दर्जा

कार्यक्रम संख्या 10: निवेश कर नीतियां

कार्यक्रम संख्या 11: पुनर्निवेश भत्ता

कार्यक्रम संख्या 12: त्वरित पूंजी भत्ता

कार्यक्रम संख्या 13: समूह राहत

कार्यक्रम संख्या 14: टैरिफ संबंधित प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 15: भत्ता औद्योगिक भवन (आईबीए)

कार्यक्रम संख्या 16: संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता

कार्यक्रम संख्या 17: मलेशियाई ब्रांड के प्रचार के लिए कर योग्य लाभ से दुगनी कटौती

कार्यक्रम संख्या 18: पूर्वी तट आर्थिक गलियारे में विनिर्माण और विनिर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 19: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क की वापसी

कार्यक्रम संख्या 21: आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम संख्या 23: मशीनरी और उपकरण पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम संख्या 24: कच्चे माल/घटकों पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात के संवर्धन के लिए कर योग्य लाभ से दोहरी कटौती

कार्यक्रम संख्या 26: निर्यात कार्गो के प्रचार के लिए कर योग्य आय पर दोहरी कटौती

कार्यक्रम संख्या 27: लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 28: बढ़े हुए निर्यात के लिए भत्ता

कार्यक्रम संख्या 29: मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए कर छूट

कार्यक्रम संख्या 30: अनुसंधान और विकास निधि

कार्यक्रम संख्या 30 (क): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ 1)

कार्यक्रम संख्या 30 (ख): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ 2)

कार्यक्रम संख्या 30 (ग): अनुसंधान और विकास कोष का व्यावसायीकरण (सीआरडीएफ 3)

कार्यक्रम संख्या 31: इन-हाउस आर एंड डी के लिए कर प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 32: अनुसंधान और विकास के लिए दोहरी कटौती

### ऋण के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 33: सावधि ऋण

कार्यक्रम संख्या 34: लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) को कम ब्याज पर ऋण

### III. थाईलैंड के संबंध में योजनाओं की सूची

अनुदान के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 1: गोल्ड कार्ड योजना

### कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 2: मशीनरी पर आयात शुल्क की छूट / कमी - निवेश संवर्धन अधिनियम की धारा 28

कार्यक्रम संख्या 3: आयकर छूट

कार्यक्रम संख्या 4: निवेश संवर्धन क्षेत्र के संबंध में छूट

कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात के लिए उत्पादन में उपयोग के लिए आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क की छूट

कार्यक्रम संख्या 6: कच्ची या आवश्यक सामग्रियों के लिए आयात शुल्क में कमी

कार्यक्रम संख्या 7: बीओआई-प्रचारित गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की छूट

कार्यक्रम संख्या 8: निवेश संवर्धन क्षेत्र में कॉर्पोरेट आयकर की 50 प्रतिशत कटौती

कार्यक्रम संख्या 9: प्रचारित क्षेत्रों में परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति की लागत की आयकर में दोहरी कटौती

कार्यक्रम संख्या 10: स्थापना की लागत या सुविधाओं के निर्माण की लागत की 25 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती

कार्यक्रम संख्या 11: कर और शुल्क मुआवजा / कर कूपन

कार्यक्रम संख्या 12: आवद्ध गोदामों के लिए आयात / निर्यात शुल्क की छूट

कार्यक्रम संख्या 13: थाईलैंड में कोई भी वहुत कम मौजूदा निवेश के साथ देश के विकास के लिए वृनियादी ढाचे में गतिविधियों, मूल्यवर्धन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 14: उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनमें कुछ निवेश पहले से ही थाईलैंड में मौजूद हैं, के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 15: प्रतिस्पर्धी संवर्द्धन में वृद्धि के लिए मेरिट आधारित प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 16: निर्यात पर वैट छूट

कार्यक्रम संख्या 17: संवर्धनात्मक विशेषाधिकार

कार्यक्रम संख्या 18: - सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के तहत छूटी ड्रावै

### 3. मुक्त व्यापार क्षेत्र योजनाओं के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 19: - सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 10 के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र

कार्यक्रम संख्या 20: औद्योगिक प्रसंस्करण प्राधिकरण कानून के तहत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड)

#### IV. वियतनाम के संबंध में योजनाओं की सूची

##### कर प्रोत्साहन और छूट के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 1: डिक्री 24 के अध्याय V के तहत आयकर प्राथमिकताएं (एंटरप्राइज़ आयकर पर कानून का कार्यान्वयन)

कार्यक्रम 2: कच्चे माल के लिए आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम संख्या 3: उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट

##### निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 5: निर्यातकों को अधिमान्य ऋण

कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

कार्यक्रम संख्या 7: वियतनाम विकास बैंक से निर्यात ऋण

कार्यक्रम संख्या 8: निर्यात समर्थन ऋण

##### निवेश प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 9: निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण

कार्यक्रम संख्या 10: निवेश क्रेडिट ऋण की ब्याज दर

कार्यक्रम संख्या 11: विदेशी निवेशकों पर जिन्होंने छोटे और मध्यम पैमाने पर उद्यम स्थापित करने पर निवेश किया को निवेश समर्थन

##### बैंकों से लाभ के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 13: वियतन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

##### विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होने के लिए अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 14: डिक्री 142 के तहत प्रोत्साहित उद्योगों या औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए भूमि वरीयताएं

##### उपयोगिताओं के उपयोग पर प्रोत्साहन के लिए अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 15: पर्यास मूल्य से कम पर भूमि का और भूमि और जल के किराए से छूट या कटौती का सरकारी प्रावधान

#### अन्य सब्सिडियां

एसबीवी के तहत ब्याज दर सहायता कार्यक्रम

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि उनमें संबंधित संबद्ध देशों की सरकारों या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों सहित सार्वजनिक निकायों से वित्तीय अंशदान शामिल हैं और प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) को लाभ प्रदान करते हैं। उनके कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूह और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित घरेलू वस्तुओं के उपयोग से जुड़े होने का आरोप है और इसलिए ये विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क योग्य हैं। उनके कुछ मामलों में आयातित वस्तुओं के मुकाबले घरेलू वस्तुओं के प्रयोग से जुड़े और/या निर्यात प्रदर्शन से जुड़े होने का आरोप है।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध और मौजूद पाया जाता है।

#### घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

7. आवेदक ने नियमों में अधीन यथा विहित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में जानकारी दी है। आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से कथित सब्सिडीप्राप्त आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

#### झ. जॉच की शुरूआत

8. और यतः, प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस तरह के सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग को उसकी मात्रा और मूल्य प्रभाव के माध्यम से क्षति का कारण बन रहे हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा सब्सिडी वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे का आरोप लगाया गया है।

9. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी संबंधित नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे की जांच की शुरूआत करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हर्दि 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### **इ. घरेलू उद्योग**

10. यह आवेदन मै. हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. वेदांता इंडस्ट्रीज (स्टरलाइट कापर) द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होने के कारण उनका कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि वर्तमान आवेदन में घरेलू उत्पादकों के घटक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

#### **ज. विचाराधीन उत्पाद**

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कांटिन्युअस कास्ट कापर वायर राइस" है जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19 के अधीन वर्गीकरण योग्य है।

#### **ज. समान वस्तु**

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये दोनों वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

#### **झ. शामिल देश**

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ शामिल देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

#### **ज. जांच अवधि**

14. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2017 – मार्च 2018 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल होगी।

#### **ट. प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करना**

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातिकों, संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई पक्षकार निम्नलिखित पते पर लिख सकता है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**वाणिज्य विभाग,**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110011**

16. संबंधित नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिकी उत्पादकों और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

### (i) समय-सीमा

17. वर्तमान जांच संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि चीन की सरकार, निर्यातक और आयातक जिन्हें अलग से लिखा गया है, को उन्हें अलग से प्रेपित पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### (ii) अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समृच्छित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### (iii) असहयोग

24. नियम 7(8) के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

### (iv) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### (v) प्रतिदर्श

26. इस कार्यवाही में शामिल चीन जन. गण. के निर्यातक उत्पादकों की संभावित भारी संख्या को देखते हुए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस जांच को पूरा करने के लिए, प्राधिकारी जांच किए जाने वाले निर्यातक उत्पादकों को प्रतिदर्श का चयन करके तर्कसंगत

संख्या तक सीमित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो प्रतिदर्श सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 17(3) के अनुसार लिए जाएंगे।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 10<sup>th</sup> September, 2018

**Case No. OI (CVD)- 04/2018**

**Subject: Initiation of Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Continuous Cast Copper Wire Rods from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam.**

**F. No.6/17/2018-DGAD:** Whereas M/s Hindalco Industries and M/s Vedanta Industries (Sterlite Copper) (hereinafter referred to as Petitioners) have filed an application on behalf of Domestic industry before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of Continuous Cast Copper Wire Rods (hereinafter referred to as the subject goods), from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

**A. Allegation of Subsidization**

2. The petitioners have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject countries, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public bodies'. The petitioners have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

**B. Consultation**

3. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of Indonesia, Government of Malaysia, Government of Thailand and Government of Vietnam. The comments of representatives of the Government of subject countries have been taken on record.

**C. Subsidy Programs**

4. The prima facie evidence provided by the petitioners shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject countries have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the Government of respective subject countries and/or their respective public bodies as listed below.

**I. List of Schemes in respect of Indonesia**

**Schemes Identified as Export Financing and Export Credit**

Program No. 2 : Export Financing from Indonesia EXIM

Program No. 3 : Exporters being reimbursed for their losses

**Schemes Identified as Loans:**

Program No. 5 : Various Loans provided by Mandiri Bank

a. Program No 5(a): Investment Loan

b. Program No 5(b) : Loan for entrepreneur

**Schemes Identified as Tax Incentives and VAT Exemption**

- Program No. 7 : Exemption on Import Duty
- Program No. 8 : Import Duty Drawback
- Program No. 9 : Income Tax on Dividend
- Program No.10: Reduction of Net Taxable Income
- Program No. 11 : Carry Forward of Losses
- Program No.12: Postponement of payment of Import Duty on importation of capital goods
- Program No. 13 : Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production Purpose
- Program No.14: Exemption from Income Tax on Imports of certain goods if the company is located in SEZ.
- Program No.15: Reduction in Income Tax for Investors investing in SEZ
- Program No.17 : Pioneer Industry Status
- Program No.18 : Income Tax benefits for listed Investments

**Schemes Identified as Provision for Goods & Services**

- Program No.20 : Deduction in Land Tax for enterprises located in SEZ.

**II. List of Schemes in respect of Malaysia**

**Schemes Identified as Grants**

- Program No.1: The Market Development grant
- Program No.2: Science Fund
- Program No.3: Techno Fund
- Program No.4: Inno Fund
- Program No.5: Cradle Investment Program
- Program No.6: Export excellence award

**Schemes Identified as Export Credit and Export Financing**

- Program No.7: Export Credit Refinancing
- Program No 8: Buyer Credit Guarantee

**Schemes Identified as Tax Incentive**

- Program No.9: Pioneer Status
- Program No.10: Investment Tax Policies
- Program No.11: Reinvestment Allowance
- Program No.12: Accelerated Capital Allowance
- Program No.13: Group Relief
- Program No.14: Tariff Related Incentives
- Program No.15: Allowance Industrial Building (IBA)
- Program No.16: Allowance for plants and Machinery
- Program No.17: Double deduction from taxable profit for promotion of Malaysian brand
- Program No.18: Incentives for manufacturing and manufacturing related services in East Coast Economic Corridor
- Program No.19: Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
- Program No.21: Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities
- Program No.23: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
- Program No.24: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
- Program No.25: Double Deduction from taxable profit for Promotion of Exports

Program No.26: Double Deduction on taxable income for Promotion of Export Cargo

Program No.27: Incentives for Small and Medium Enterprises

Program No.28: Allowance for Increased Export

Program No.29: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

Program No 30 : Research and Development fund

Program No.30 (a) : Commercialization of Research and Development Fund (CRDF 1)

Program No.30 (b) : Commercialization of Research and Development Fund (CRDF 2)

Program No.30 (c) : Commercialization of Research and Development Fund (CRDF 3)

Program No.31: Tax incentives for in-house R&D

Program No.32: Double Deduction for Research and Development

**Schemes Identified as Loans**

Program No.33: Term Loans

Program No.34: Soft loans to Small and medium Enterprise (SMEs)

**III. List of Schemes in respect of Thailand**

**Schemes Identified as Grants**

Program No. 1: Gold Card Scheme

**Schemes Identified as Tax and VAT Incentives**

Program No. 2: Exemption/Reduction of Import Duties on Machinery – Section 28 of Investment Promotion Act

Program No 3 Income Tax Exemption

Program No 4: Exemptions with regard to investment promotion zone

Program No. 5:Exemption of Import duty on Raw Material Imported for use in Production for Export

Program No. 6 : Reduction of Import Duty for Raw or Essential Materials

Program No. 7 : Exemption of Corporate Income Tax for BOI-Promoted Activities

Program No. 8 : A 50 Percent Reduction of the Corporate Income tax in Investment Promotion Zones

Program No. 9 : Income Tax Double Deduction of the costs of Transportation, Electricity and Water supply in Promoted Zones

Program No. 10 : Additional 25 percent Deduction of the Cost of Installation or Construction of Facilities

Program No. 11: Tax and Duty Compensation/Tax coupons

Program No.12: Exemption of Import/Export duty for Bonded Warehouses

Program No.13: Incentives for Activities in Infrastructure for the Country's development, activities using Advanced Technology to create value added with no or very few existing Investments in Thailand

Program No.14: Incentives for High Technology Activities which are important to the country's development, with a few Investments already existing in Thailand

Program No.15: Merit based Incentive for Increase in Competitive Enhancement

Program No.16: VAT Exemption on Exports

Program No.17: Promotional Privileges

Program No 18:- Duty Drawback under Section 19 of the Customs laws

**Schemes Identified in the form of free trade zone Schemes**

Program No 19:- Free trade zone under Chapter X of the Customs act

Program No 20: Export processing zone (EPZ) Under the Industrial Estate Authority law

#### **IV. List of Schemes in respect of Vietnam**

##### **Schemes Identified as Tax Incentives and Exemptions**

Program No 1: Income Tax Preferences under Chapter V of Decree 24 (Implementation of the Law on Enterprise Income Tax)

Program 2: Import duty exemption or reimbursement for raw material

Program No 3: Exemption on corporate income tax for enterprises

##### **Schemes Identified as export financing and Export Credit**

Program No 5: Preferential lending to exporters

Program No 6: Export Promotion Program

Program No.7: Export Credits from Vietnam Development Bank

Program No.8: Export Support Credit

##### **Schemes Identified as Investment Incentives**

Program No. 9: Preferential lending for investors

Program No. 10: Interest rate of investment credit loans

Program No. 11: On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises

##### **Schemes Identified as benefits from Bank**

Program No. 13: Financial guarantee by Vietin Bank

##### **Schemes Identified for being located in specific Zones**

Program No. 14: Land preferences for enterprises in encouraged industries or Industrial zones under decree 142

##### **Schemes Identified for incentives on use of utilities**

Program No. 15: Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land and water rents

##### **Other Subsidies**

Interest Rate Support Program under the SBV.

5. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the respective subject countries or other regional or local governments of such respective countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance
6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

##### **Allegation of Injury and Casual Link**

7. The petitioners have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioner's *prima facie* shows material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject countries.

##### **Initiation of the Investigation**

8. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects. Further the threat of material injury to the domestic industry on account of subsidized imports has also been alleged by the domestic industry.
9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **Domestic Industry**

10. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Limited and M/s Vedanta Industries (Sterlite Copper) as per the evidence available on record, production of the petitioners accounts for major proportion of the total domestic production. The Authority, therefore, determines that the constituent of domestic producers in the present application constitute domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rules 6(3) of the Rules supra.

### **Product under consideration**

11. The product under consideration in the present investigation is “Continuous Cast Copper Wire Rods” classifiable under custom sub headings 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11, 7409.19

### **Like Article**

12. The petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from subject countries. The petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like articles’ of the subject goods imported from the subject countries.

### **Countries Involved**

13. The countries involved for the purpose of current investigation are Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam

### **Period of Investigation**

14. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2017 to March, 2018 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

## **K. Procedure & Submission of information**

15. The exporters in the subject countries, importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to provide all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

### **The Designated Authority**

#### **Directorate General of Trade Remedies**

#### **Department of Commerce**

#### **Ministry of Commerce & Industry**

#### **4th Floor, Jeevan Tara Building,**

#### **5 Parliament Street, New Delhi – 110001**

16. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to represent consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limits set out below.

#### **(i) Time limit**

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of subject countries, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

#### **(ii) Submission of Information on Non-Confidential basis**

18. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire’s response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as

Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non- confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

**(iii) Non cooperation**

24. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**(iv) Inspection of Public File**

25. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**(v) Sampling**

26. In view of the possibility of participation by large number of exporter(s)/producer(s) in the subject countries involved in this proceeding and the limited time period for completion of the investigation, the Authority may limit the exporter(s)/producer(s) to be investigated to a reasonable number by selecting a sample. The sampling shall be carried out, if required, in terms of Rule 17(3) of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General